



माध्यमिक स्तर की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि पर लैंगिक असमानता का प्रभाव चंदौली जिले का अध्ययन

पुष्पांजलि मिश्रा¹ मंजू अग्निहोत्री²

¹शोधार्थी, ²शोध निर्देशक

^{1,2}शिक्षा विभाग, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायसेन

1. प्रस्तावना

शिक्षा बालिका को ज्ञान, निर्णय क्षमता, आर्थिक अवसर और सामाजिक भागीदारी प्रदान करती है। भारतीय संविधान समानता तथा शिक्षा का अधिकार देता है, फिर भी विद्यालय और परिवार में कार्य विभाजन, सुरक्षा संबंधी आशंका, कम आयु में विवाह, घरेलू श्रम और संसाधनों की असमान उपलब्धता बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समान अवसर, सुरक्षित विद्यालय और लैंगिक समावेशन को विद्यालयी सुधार का आधार माना है [1]। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की कानूनी व्यवस्था की, किंतु माध्यमिक स्तर तक पहुँच और निरंतरता में क्षेत्रीय तथा सामाजिक अंतर बने हुए हैं [2]।

विद्यालयी शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आँकड़े बताते हैं कि नामांकन में सुधार के साथ-साथ उपस्थिति, संक्रमण और सीखने के परिणामों पर ध्यान देना आवश्यक है [3]। समग्र शिक्षा योजना बालिका छात्रावास, परिवहन, आत्मरक्षा, अलग शौचालय और समुदाय आधारित जागरूकता जैसे उपायों को जोड़ती है [4]। नई पाठ्यचर्या रूपरेखा भी पाठ्यपुस्तक, कक्षा व्यवहार और मूल्यांकन में लैंगिक रूढ़ियों को कम करने की अपेक्षा करती है [5]। इस प्रकार समानता केवल विद्यालय में नाम लिख जाने तक सीमित नहीं है; उसका संबंध विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सहभागिता, उपलब्धि और आगे पढ़ने की आकांक्षा से है।

पारिवारिक सामाजिक उपभोग के आँकड़ों में दूरी, लागत, घरेलू उत्तरदायित्व और परिवार की धारणा को विद्यालय छोड़ने के कारणों में महत्वपूर्ण पाया गया है [6]। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने महिला शिक्षा, विवाह की आयु और निर्णय क्षमता के बीच संबंधों की ओर संकेत किया है [7]। ग्रामीण शिक्षा की वार्षिक स्थिति संबंधी प्रतिवेदन सीखने के स्तरों में व्यापक अंतर दिखाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि केवल कक्षा में बने रहना पर्याप्त नहीं है [8]। जब बालिका को पढ़ाई का समय, शांत स्थान, पुस्तकें, आवागमन और परिवार का



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सहयोग कम मिलता है, तब समान पाठ्यक्रम के बावजूद उपलब्धि में अंतर उत्पन्न हो सकता है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी प्रतिवेदन ने समावेशन को शिक्षा व्यवस्था की संरचना, संसाधन वितरण और विद्यालयी संस्कृति से जोड़ा है [9]। शिक्षा में लैंगिक समानता पर यूनेस्को के विश्लेषण में विद्यालय तक पहुँच, नेतृत्व, पाठ्यक्रम और सीखने के परिणामों को एक साथ देखने की आवश्यकता बताई गई है [10]। यूनिसेफ ने किशोरियों के लिए सुरक्षित आवागमन, जीवन कौशल, मासिक धर्म स्वच्छता और परिवार से संवाद को निरंतरता के प्रमुख आधार माना है [11]। विश्व बैंक के अनुसार बालिका शिक्षा में कमी का प्रभाव व्यक्तिगत आय के साथ समाज के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर भी पड़ता है [12]। सतत विकास लक्ष्य चार और पाँच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा लैंगिक समानता को परस्पर जुड़ा हुआ लक्ष्य मानते हैं [13]।

सेन ने विकास को वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में समझाया है; शिक्षा बालिका को उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने की क्षमता देती है [14]। नुसबाम का क्षमता दृष्टिकोण सम्मान, शारीरिक सुरक्षा और निर्णय की स्वतंत्रता को शिक्षा के परिणामों से जोड़ता है [15]। किंग और हिल ने महिला शिक्षा के पारिवारिक तथा सामाजिक लाभों को प्रमाणों के आधार पर रेखांकित किया [16]। क्लासेन ने शिक्षा में लैंगिक असमानता को आर्थिक वृद्धि की धीमी गति से संबद्ध पाया [17]। हर्ज और स्पर्लिंग ने स्पष्ट किया कि बालिका शिक्षा में निवेश के लाभ पीढ़ियों तक दिखाई देते हैं [18]।

अंतरहाल्टर ने चेताया कि केवल नामांकन अनुपात से समानता का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता [19]। स्ट्रामक्विस्ट ने शिक्षा को सशक्तीकरण की प्रक्रिया माना, किंतु विद्यालय के भीतर सत्ता संबंधों और रूढ़ियों की समीक्षा को आवश्यक बताया [20]। भारत संबंधी अध्ययनों में बंधोपाध्याय और सुब्रह्मण्यम ने जाति, वर्ग, क्षेत्र और लिंग के संयुक्त प्रभाव पर बल दिया [21]। गोविंदा और बंधोपाध्याय ने विद्यालयी बहिष्करण को प्रवेश, उपस्थिति और सीखने के कई स्तरों पर घटित होने वाली प्रक्रिया बताया [22]। रामचंद्रन ने विद्यालयी व्यवस्था में सुरक्षा, शौचालय, शिक्षक व्यवहार और सामाजिक अपेक्षाओं को बालिका शिक्षा से जुड़ा पाया [23]।

ट्रेज और किंगडन के ग्रामीण भारत संबंधी अध्ययन में पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यालय की उपलब्धता और सामाजिक पहचान ने भागीदारी को प्रभावित किया [24]। मुरलीधरन और प्रकाश ने सुरक्षित आवागमन हेतु साइकिल कार्यक्रम से बालिकाओं के माध्यमिक नामांकन में वृद्धि दिखाई [25]। जेन्सेन ने रोजगार अवसरों की जानकारी से किशोरियों की शिक्षा और



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

विवाह संबंधी निर्णयों में बदलाव पाया [26]। दुफ्लो ने महिला सशक्तीकरण और विकास के बीच संबंध को महत्वपूर्ण माना, पर यह भी बताया कि दोनों के बीच संबंध स्वतः नहीं बनता [27]। असदुल्लाह और चौधरी ने विद्यालय प्रकार और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार उपलब्धि अंतर की चर्चा की [28]। हनुशेक और वुसमैन ने शिक्षा की गुणवत्ता को दीर्घकालीन विकास का निर्णायक आधार माना [29]। भारतीय ग्रामीण संदर्भ में बालिकाओं की आकांक्षाएँ परिवार और समुदाय की अपेक्षाओं से प्रभावित होती हैं [30]।

चंदौली जिले में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों, शासकीय और अशासकीय विद्यालयों तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों की उपस्थिति इस प्रश्न को स्थानीय स्तर पर जाँचने की आवश्यकता उत्पन्न करती है। प्रस्तुत अध्ययन में लैंगिक असमानता को घरेलू कार्यभार, निर्णय में भागीदारी, शैक्षिक संसाधन, सुरक्षा, विद्यालयी व्यवहार और भविष्य की अपेक्षाओं से निर्मित अनुभव के रूप में मापा गया है। शैक्षिक उपलब्धि के लिए पूर्व कक्षा के प्राप्तांकों का उपयोग किया गया है। अध्ययन का केंद्र यह जानना है कि असमानता का स्तर बढ़ने पर उपलब्धि में कितना परिवर्तन आता है और क्या स्थान तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति इस संबंध को बदलते हैं।

2. उद्देश्य

1. माध्यमिक स्तर की बालिकाओं में लैंगिक असमानता के अनुभव और शैक्षिक उपलब्धि का स्तर ज्ञात करना।
2. उच्च और निम्न लैंगिक असमानता अनुभव करने वाली बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करना।
3. लैंगिक असमानता, निवास क्षेत्र तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि के संबंध का परीक्षण करना।

3. परिकल्पनाएँ

1. उच्च और निम्न लैंगिक असमानता अनुभव करने वाली बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
2. ग्रामीण और नगरीय बालिकाओं के लैंगिक असमानता प्राप्तांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
3. लैंगिक असमानता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं होगा।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

4. शोध प्रविधि

4.1 शोध विधि

अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि अपनाई गई। यह विधि बालिकाओं के वर्तमान अनुभव, विद्यालयी परिस्थितियों और उपलब्धि के बीच संबंध का मापन करने के लिए उपयुक्त है।

4.2 न्यादर्श

चंदौली जिले के आठ माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा नौवीं और दसवीं की 100 बालिकाएँ स्तरीकृत यादृच्छिक चयन से ली गईं। इनमें 50 ग्रामीण और 50 नगरीय क्षेत्र से थीं। प्रत्येक क्षेत्र में शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया।

4.3 उपकरण

लैंगिक असमानता अनुभव मापनी में 30 कथन रखे गए। विषय विशेषज्ञों से विषयवस्तु वैधता प्राप्त की गई। प्रारंभिक परीक्षण में आंतरिक संगति गुणांक 0.86 मिला। सामाजिक आर्थिक सूचना पत्रक और पूर्व कक्षा के वार्षिक परीक्षा प्राप्तांक भी संकलित किए गए।

4.4 आँकड़ा संग्रह

विद्यालय प्रमुख की अनुमति और प्रतिभागियों की सहमति के बाद समूह रूप में मापनी प्रशासित की गई। उत्तर गोपनीय रखे गए। अनुपस्थित छात्राओं के लिए दूसरी तिथि निर्धारित की गई। वार्षिक प्राप्तांक विद्यालय अभिलेख से सत्यापित किए गए।

4.5 सांख्यिकीय विश्लेषण

आवृत्ति, प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन, स्वतंत्र नमूना माध्यांतर परीक्षण, पियर्सन सहसंबंध और सरल प्रतिगमन का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष के लिए 0.05 महत्व स्तर स्वीकार किया गया।

5. परिणाम

तालिका 1 प्रतिभागियों का वितरण

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	50	50.0
नगरीय	50	50.0
कक्षा नौवीं	48	48.0
कक्षा दसवीं	52	52.0
कुल	100	100.0



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

न्यादर्श में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का समान प्रतिनिधित्व है। कक्षा नौवीं और दसवीं की संख्या में बहुत कम अंतर है, इसलिए कक्षा संरचना किसी एक समूह की ओर अत्यधिक झुकी हुई नहीं है।

तालिका 2 लैंगिक असमानता और शैक्षिक उपलब्धि का वर्णन

चर	माध्य	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम
लैंगिक असमानता	72.46	13.18	41	103
शैक्षिक उपलब्धि	66.82	10.74	42	89

लैंगिक असमानता प्राप्तांकों का प्रसार पर्याप्त है, जिससे न्यादर्श में अनुभवों की विविधता स्पष्ट होती है। उपलब्धि का माध्य 66.82 प्रतिशत है और मानक विचलन 10.74 है।

तालिका 3 असमानता स्तर के अनुसार उपलब्धि

समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलन	माध्यांतर मान
निम्न असमानता	50	72.18	8.42	5.86
उच्च असमानता	50	61.46	10.11	

निम्न असमानता समूह का उपलब्धि माध्य उच्च असमानता समूह से 10.72 अंक अधिक है। प्राप्त माध्यांतर मान 5.86 है, जो 0.05 स्तर पर सार्थक है। पहली शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हुई।

तालिका 4 निवास क्षेत्र के अनुसार लैंगिक असमानता

क्षेत्र	संख्या	माध्य	मानक विचलन	माध्यांतर मान
ग्रामीण	50	77.32	12.06	3.92
नगरीय	50	67.6	12.71	

ग्रामीण बालिकाओं का असमानता माध्य नगरीय बालिकाओं से 9.72 अंक अधिक है। माध्यांतर मान 3.92 सार्थक है। दूसरी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हुई।

तालिका 5 लैंगिक असमानता और उपलब्धि का सहसंबंध

चर युग्म	सहसंबंध गुणांक	निर्धारण प्रतिशत	निर्णय
असमानता और उपलब्धि	-0.58	33.64	सार्थक ऋणात्मक संबंध



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सहसंबंध गुणांक -0.58 मध्यम से प्रबल ऋणात्मक संबंध दर्शाता है। असमानता में वृद्धि के साथ उपलब्धि घटती है। निर्धारण प्रतिशत से संकेत मिलता है कि उपलब्धि में लगभग एक तिहाई परिवर्तन असमानता प्राप्तांकों से संबद्ध है। तीसरी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हुई।

तालिका 6 सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार उपलब्धि

स्तर	संख्या	माध्य	मानक विचलन
निम्न	31	60.84	9.62
मध्यम	47	67.51	9.18
उच्च	22	73.77	8.05

सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ने के साथ उपलब्धि माध्य भी बढ़ा। यह परिणाम बताता है कि लैंगिक अनुभवों के साथ संसाधन, अध्ययन का समय और शैक्षिक सहयोग भी उपलब्धि से जुड़े हैं।

प्रतिगमन विश्लेषण में लैंगिक असमानता का मानकीकृत प्रभाव ऋणात्मक पाया गया। निवास क्षेत्र और सामाजिक आर्थिक स्थिति को साथ रखने पर भी असमानता का प्रभाव बना रहा। इसका अर्थ कारण सिद्ध करना नहीं है, किंतु यह संबंध इतना स्पष्ट है कि विद्यालय और परिवार दोनों स्तरों पर हस्तक्षेप आवश्यक दिखाई देता है।

6. निष्कर्ष

अध्ययन में उच्च लैंगिक असमानता अनुभव करने वाली बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि स्पष्ट रूप से कम पाई गई। ग्रामीण बालिकाओं का असमानता प्राप्तांक अधिक था और सामाजिक आर्थिक स्तर के साथ उपलब्धि में क्रमिक वृद्धि दिखाई दी। इससे पता चलता है कि बालिका शिक्षा की समस्या केवल प्रवेश से संबंधित नहीं है; घरेलू कार्यभार, पढ़ाई के संसाधन, आवागमन, सुरक्षा, निर्णय में भागीदारी और विद्यालयी व्यवहार मिलकर उपलब्धि को प्रभावित करते हैं।

विद्यालयों में सुरक्षित आवागमन, कार्यशील अलग शौचालय, शिकायत व्यवस्था, परामर्श और लैंगिक संवेदनशील कक्षा व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अभिभावक बैठकों में बालिकाओं के अध्ययन समय और घरेलू कार्य के संतुलन पर स्पष्ट चर्चा हो। आवश्यकता आधारित छात्रवृत्ति, पुस्तक सहायता और नियमित उपस्थिति की निगरानी ग्रामीण तथा निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए विशेष उपयोगी होगी।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

अध्ययन का न्यादर्श 100 बालिकाओं तक सीमित है और निष्कर्ष स्वप्रतिवेदित अनुभवों तथा विद्यालयी प्राप्तांकों पर आधारित हैं। व्यापक सामान्यीकरण से पहले अधिक विद्यालयों और दीर्घकालीन आँकड़ों पर अध्ययन आवश्यक है। फिर भी प्राप्त परिणाम चंदौली जिले में लैंगिक असमानता और शैक्षिक उपलब्धि के संबंध को स्थानीय प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं।

संदर्भ सूची

- [1] भारत सरकार, 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
- [2] भारत सरकार, 2009. बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
- [3] शिक्षा मंत्रालय, 2024. विद्यालयी शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 2023-24. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- [4] शिक्षा मंत्रालय, 2023. समग्र शिक्षा की रूपरेखा. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- [5] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2023. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा. नई दिल्ली।
- [6] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 2020. भारत में शिक्षा संबंधी पारिवारिक सामाजिक उपभोग सर्वेक्षण. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- [7] अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, 2021. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पांच. मुंबई।
- [8] प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान, 2023. शिक्षा की वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन ग्रामीण. नई दिल्ली।
- [9] यूनेस्को, 2020. वैश्विक शिक्षा निगरानी प्रतिवेदन में समावेशन और शिक्षा. पेरिस।
- [10] यूनेस्को, 2022. शिक्षा में लैंगिक समानता पर गहन प्रतिवेदन. पेरिस।
- [11] यूनिसेफ, 2021. भारत में किशोरियों की शिक्षा और सशक्तीकरण. नई दिल्ली।
- [12] विश्व बैंक, 2018. अवसरों का अभाव और बालिका शिक्षा की वैश्विक लागत. वाशिंगटन।
- [13] संयुक्त राष्ट्र, 2015. सतत विकास हेतु 2030 कार्यसूची. न्यूयार्क।
- [14] सेन, अमर्त्य, 1999. स्वतंत्रता के रूप में विकास. नई दिल्ली: आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- [15] नुसबाम, मार्था, 2000. महिलाएँ और मानव विकास. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- [16] किंग, एलिजाबेथ और हिल, ऐन, 1993. विकासशील देशों में महिला शिक्षा. बाल्टिमोर: जान्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय प्रकाशन।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

- [17] क्लासेन, स्टीफन, 2002. शिक्षा में लैंगिक असमानता और आर्थिक वृद्धि. विश्व बैंक आर्थिक समीक्षा, 16, 345-373।
- [18] हर्ज, बारबरा और स्पलिंग, जीन, 2004. लड़कियों की शिक्षा से विकास के लाभ. न्यूयार्क: विदेश संबंध परिषद।
- [19] अंतरहाल्टर, इलेन, 2005. शिक्षा में लैंगिक समानता और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य. तुलना, 35, 111-126।
- [20] स्ट्रामक्विस्ट, नेली, 2015. महिला शिक्षा और सशक्तीकरण की पुनर्व्याख्या. शिक्षा की समाजशास्त्रीय समीक्षा, 26, 307-324।
- [21] बंधोपाध्याय, माधुमिता और सुब्रह्मण्यम, राम्या, 2008. भारत में शिक्षा में लैंगिक समानता. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय।
- [22] गोविंदा, रंगाचार्य और बंधोपाध्याय, माधुमिता, 2011. भारत में विद्यालयी भागीदारी और बहिष्करण. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय।
- [23] रामचंद्रन, विमला, 2004. भारत में लैंगिक असमानता और विद्यालयी शिक्षा. नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
- [24] द्रेज, ज्यां और किंगडन, गीता, 2001. ग्रामीण भारत में विद्यालयी भागीदारी. विकास अध्ययन समीक्षा, 5, 1-24।
- [25] मुरलीधरन, कार्तिक और प्रकाश, निशीथ, 2017. साइकिल से विद्यालय तक बालिका शिक्षा कार्यक्रम का प्रभाव. अमेरिकी आर्थिक पत्रिका, 9, 321-350।
- [26] जेन्सेन, राबर्ट, 2012. श्रम बाजार अवसर और युवतियों की शिक्षा. त्रैमासिक अर्थशास्त्र पत्रिका, 127, 753-792।
- [27] दुफ्लो, एस्थर, 2012. महिला सशक्तीकरण और आर्थिक विकास. आर्थिक साहित्य पत्रिका, 50, 1051-1079।
- [28] असदुल्लाह, मुहम्मद और चौधरी, नजमुल, 2009. विद्यालय चयन और लैंगिक उपलब्धि अंतर. शिक्षा अर्थशास्त्र समीक्षा, 28, 75-86।
- [29] हनुशेक, एरिक और वुसमैन, लुद्विग, 2008. शिक्षा की गुणवत्ता और आर्थिक विकास. आर्थिक साहित्य पत्रिका, 46, 607-668।
- [30] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2019. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन दिशानिर्देश. नई दिल्ली: भारत सरकार।